

13. उद्योग

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014-2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

● आयोजना बजट सीलिंग राशि	112.65 लाख
● राज्य आयोजना मद	112.65 लाख
● केन्द्रीय योजना मद	शुन्य

लक्ष्य एवं उदेश्य

- बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना ।
- बुनकरों एवं दस्तकारों के विकास हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन ।
- महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित कर गृह उद्योग स्थापित करवाना ।
- नमक मजदूरों की आवास समस्याओं के निराकरण हेतु आवास निर्माण करवाना ।
- नमक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना

m | ksx foHkkx dk nf"V i =

12-1 orĕku fLFkfr

जिला उद्योग केन्द्र का मुख्य कार्य गैरकृषिगत आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके क्षेत्र के आर्थिक विकास को समृद्ध करना एवं निजी क्षेत्रों में नियोजन की संभावनाओं में वृद्धि करना है। नागौर जिला मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिला है वर्तमान में भी जिले की अधिकांश मानवशक्ति कृषि एवं इसकी सहायक गतिविधियों में लिप्त है। जिले में 06 वृहद एवं मध्यम स्तरीय उद्यम तथा 8 हजार से अधिक लघु उद्यमों एवं 8.5 हजार हस्तशिल्प उद्यमों में लगभग 65 से 70 हजार कार्यशील युवाओं को रोजगार दिया हुआ है। जिले में मार्बल एवं सैण्ड स्टोन जैसे इमारती पत्थरों के अलावा खाद्य नमक, लिग्नाइट, लाईम स्टोन, क्ले आदि बहुमूल्य खनिज सम्पदा अधिशेष है, कृषि प्रधान जिला होने के कारण यहां पर खाद्य प्रसंस्करण कृषि उपज ग्रेडिंग एवं पैकिंग उद्योग स्थापना की भी विपुल संभावना है ताकि क्षेत्र में उत्पादित कृषि जिन्सों एवं खनिज सम्पदा मूल्य संवर्धन के पश्चात ही जिले के बाहर जावे जिससे जिले में आर्थिक गतिविधियां समर्थ हो सकें। इसके अलावा जिले में प्रतिवर्ष 5 हजार नवयुवा रोजगार हेतु प्रयास करने वालों की लम्बी प्रतीक्षा सूची में शामिल हो जाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस जिले का विभागीय योजना तैयार की गयी है।

12-1-1 ftys ea LFKkfi r m | ksxka dk foj .k

क्र.स.	इकाई का प्रकार	पंजीकृत सं०	नियोजन	विनियोजन (लाख रु०में)
1	वृहद् एवं मध्यम उद्योग	06	578	14892.53
2	लघु उद्योग	8162	40901	14390.54
3	दस्तकारी उद्योग	8589	21402	370.82

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2006 से अति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 लागू कर पंजीयन प्रणाली को समाप्त कर दिया है। एवं उद्योगों की अवधारणा "उद्यम" में समाहित कर सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर लिये जा रहा है तथा पंजीकरण की प्रणाली समाप्त कर उद्यमिता ज्ञापन पावती प्रणाली (Enterprenures memorandum acknowledgement system) लागू कर दी है। इस वित्तीय वर्ष में 825 के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 400 इकाइयों के उद्यमिता ज्ञापन जारी किये जा चुके हैं।

12-1-2 jhdks }kjk fodfl r vks| kfxd {ks=

Ø-	vks kfxd {ks=	djy {ks=Qy	djy lykV I -	lykV vkoVr I a	fjDr lykV I -
1	रीको औ.क्षेत्र नागौर	30.30 एकड	98	96	02
2	रीको औ.क्षेत्र मेडतासिटी	31.34 एकड	83	83	—
3	रीको औ.क्षेत्र मकराना	201.02 एकड	348	348	—
4	I I D रीको औ.क्षेत्र नागौर	41.53 एकड	265	224	41
5	डी.आई.सी औ.क्षेत्र गोटेन	50 बीघा	24	24	—
6	डी.आई.सी. औ.क्षेत्र बडू	25 बीघा	64	64	—
7	रीको औ.क्षेत्र डीडवाना	77.56 एकड	123	30	93

8	रीको औ.क्षेत्र परबतसर	86.86 एकड	124	115	9
9	डी.आई.सी. औ.क्षे. लाडनू	101.5 बीघा	104	98	6

12-1-3ftys eami yC/k [kfut l E ink &

नागौर की धरती केवल प्रतीक रूप में ही रत्नगर्भा नहीं है अपितु यथार्थ में भी यहाँ खनिज का प्राचुर्य है, जो यहां की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। नागौर जिले में कुल 10 तहसीलें हैं। नागौर जिले में खान एवं भू विज्ञान विभाग, के दो खनि अभियन्ता कार्यालय क्रमशः मकराना एवं नागौर तथा एक सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय गोटन में कार्यरत है। कार्यालय खनि अभियन्ता, नागौर के क्षेत्राधिकार में नागौर जिले की पांच तहसील नागौर, खींवसर, जायल, डीडवाना व लाडनू आती है। इसी तरह से खनि अभियन्ता मकराना के अधीन मकराना, परबतसर व नावां तहसील आती है। सहायक खनि अभियन्ता, गोटन (जो कि ख.अ., नागौर के अधीनस्थ है) के अधीन मेड़ता व डेगाना तहसील आती है। जिले में कुल 11 पंचायत समितियां हैं जिनका पंचायत समितिवार विवरण निम्न प्रकार से है –

1. **मकराना** : मकराना में मुख्यतया खनिज, विश्व प्रसिद्ध मार्बल, चिनाई पत्थर उपलब्ध है। मकराना का विश्व प्रसिद्ध मार्बल पुरे भारतवर्ष व कई देशों में निर्यात किया जाता हैं।
2. **परबतसर** : परबतसर के मुख्यतया खनिज, मार्बल, चिनाई पत्थर व चूना पत्थर उपलब्ध है। मार्बल पुरे भारत वर्ष व कई देशों में निर्यात किया जाता हैं।
3. **कुचामन** : कुचामन में मुख्यतया खनिज, चिनाई पत्थर उपलब्ध है। जो ग्राम जसराना, देव डूंगरी, कोटडा लाम्बा, कुचामन, गोविन्दी, हुडील, सिंगिया, पनवाड़ी व घाटवा इत्यादि में प्रचुर मात्रा में है।
4. **मेड़ता** : मेड़ता में मुख्यतया खनिज, चिनाई पत्थर, लाईम स्टोन, लिग्नाईट, क्ले आदि उपलब्ध है।
5. **रियां** : रियां में मुख्यतया खनिज चिनाई पत्थर आदि उपलब्ध है।
6. **डेगाना** : डेगाना में मुख्यतः खनिज चिनाई पत्थर व टंगस्टन आदि है।
7. **नागौर** : नागौर में मुख्य खनिज जिप्सम, लाईम स्टोन व चिनाई पत्थर उपलब्ध है।
8. **मूण्डवा** : मूण्डवा में मुख्यतया खनिज क्ले, लिग्नाईट, लाईम स्टोन एवं चिनाई पत्थर आदि उपलब्ध है।
9. **जायल** : जायल में मुख्यतया लिग्नाईट, जिप्सम, लाईम स्टोन सेण्ड स्टोन, चिनाई पत्थर, क्ले एवं रैड ऑकर आदि उपलब्ध है।
10. **डीडवाना** : डीडवाना में मुख्यतः खनिज चिनाई पत्थर तथा लाईम कंकर उपलब्ध है।
11. **लाडनू** : लाडनू में मुख्यतया खनिज चिनाई पत्थर उपलब्ध है।

12-2 ;kstuk vof/k grq y{; , oa mns' ;

- हस्तशिल्पियों के उत्पादों को विश्व बाजार उपलब्ध करवाना
- बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाना
- बुनकरों एवं दस्तकारों के विकास हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन
- महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित कर गृह उद्योग स्थापित करवाना
- नमक मजदूरों की आवास समस्याओं के निराकरण हेतु आवास निर्माण करवाना
- नमक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करना

12-3 y{; k& rd i gpus dh : i js[kk , oa j .kuhfr

- वर्तमान में मार्बल उद्योग मुख्यतः फर्श में काम आने वाली टाइल्स एवं स्लेब्स निर्माण पर सकेन्द्रित है। सैन्टरी टाइल्स निर्माण क्षेत्र में परिष्करण के पश्चात इस उद्योग को बहुत तगडी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड रहा है एवं टाइल्स व स्लेब के विपणन की समस्याएं दिन व दिन गहराती जा रही है। इसी प्रकार जिले के खाटू क्षेत्र से निकलने वाले सैण्ड स्टोन बिना किसी परिष्करण के बड़े- बड़े ब्लाक के आकार में निर्यात किया जा रहा हैं। जिससे इस बहुमूल्य सम्पदा का उचित मूल्य नहीं मिल पाता हैं। अतः इन दोनो बहुमूल्य पत्थरो को हस्तशिल्पियों के माध्यम से उत्कृष्ट कलाकृतियों तैयार करवा कर निर्यात करवाया जावे तो मूल्य संवर्धन के साथ-साथ जिले के हजारो बेरोजगार युवाओ को काम भी मिल सकेगा । इस हेतू दो प्रयास अपेक्षित है :-
 - हस्तशिल्प निर्माण हेतू स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जिसमें निरंतर डिजायन विकास करने वाले सृजको को भी शामिल किया जावे।
 - मकराना एवं खाटू के लिए उपयुक्त स्थान पर मेघाहाईवे पर पत्थर मण्डी का विकास।
- बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार प्रदान करने हेतू विस्तृत तौर पर प्रचार प्रसार कर बैरोजगार युवाओ को आकर्षित कर विभागीय योजनाओ के तहत युवाओ में उद्यमिता लक्षण का विकास कर बैको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा स्वरोजगार प्रदान किया जावेगा । जिससे युवा अपना स्वरोजगार प्रारम्भ कर विकास की धारा में शामिल हो सकेगा ।
- जिले में कार्यरत बुनकरो एवं दस्ताकारो को लाभान्वित करने हेतू विभागीय योजनाओ के तहत बुनकर एवं दस्तकारो के कलस्टर में औद्योगिक प्रोत्साहन कैम्पो का आयोजन कर बुनकरो एवं दस्तकारो को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए करघाघर अनुदान एवं ऋण उपलब्ध करवाने के आवेदन पत्र तैयार करवाये जावेगे जिन्हे विभागीय स्तर पर उपलब्ध बजट राशि एवं बैको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा लाभान्वित करवाया जावेगा
- ग्रामीण व शहरी बेरोजगार गरीब महिलाओ को स्वरोजगार हेतू स्वयं सेवी संस्थाओ से सम्पर्क कर उनके माध्यम से विभिन्न टेडस में प्रशिक्षण आयोजित करवा प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जायेगा तथा प्रशिक्षित महिलाओ को बैको के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवा रोजगार प्रदान किया जावेगा ।
- नागौर जिले के नांवा तहसील में नमक उत्पादन उद्योग में कार्यरत मजदूर जिनके पास स्वयं का मकान नहीं है उन्हे आवास उपलब्ध करवाने हेतू विभाग द्वारा पंचवर्षीय योजना में बजट प्रावधान किया गया है जिसके तहत निशुल्क भूमि उपलब्ध करवाते हुए ऋण उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान किया गया है फलतः कार्यरत मजदूरो को आवास उपलब्ध करवाये जावेगे ।
- नागौर जिले के नांवा तहसील में नमक उद्योग क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओ का अभाव होने के कारण नमक उत्पादन क्षेत्र में सडक निर्माण व अन्य सुविधाए प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवायी जावेगी।

12-4 foHkkxh; dk; Øe , Ø l pkfyr ; kst uk, a

विभाग का मुख्य कार्य जिले में औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना औद्योगिक गतिविधियों का पंजीयन करना एवं औद्योगिक गतिविधियों से सम्बन्धित विभागो में सामन्जस्य स्थापित करना। विभाग द्वारा संचालित योजनाओ का विवरण इस प्रकार है -

9-4-1 m|ferk Kki u i korh iz kkyh ½Enterprenures memorandum acknowledgement system½ &

भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2006 से अतिसूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 लागू कर पंजीयन प्रणाली को समाप्त कर दिया है। एवं उद्योगों की अवधारणा "उद्यम" में समाहित कर सेवा क्षेत्र को भी इसमें शामिल कर दिया है तथा पंजीकरण की प्रणाली समाप्त कर उद्यमिता ज्ञापन पावती प्रणाली (Enterprenures memorandum acknowledgement system) लागू कर दी है।

9-4-2 i /kkuea=h jkst xkj ; kst uk

इस योजना में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक रूप से लाभकारी गतिविधि प्रारम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंको के माध्यम से 5.00 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजनान्तर्गत चयनित युवाओं को आर्थिक गतिविधि के सफल संचालन हेतु 10-15 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है, साथ ही 15 प्रतिशत अनुदान की भी सुविधा है। अनुदान की अधिकतम सीमा प्रति लाभार्थी 12,000/- है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में 860 लक्ष्यों के विरुद्ध विभिन्न बैंकों द्वारा 477 स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है तथा 251 अभियार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर 134 युवाओं को रु. 80.40 लाख की राशि वितरित की जा चुकी है।

; kst uk fØ; kko; u dh dfBukbl nij djus grq l pko & वर्तमान में योजना के तहत मात्र राष्ट्रीयकृत बैंको द्वारा ही वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है। जिले के अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। जहां पर कभी भी राष्ट्रीयकृत बैंको की सेवाओं का विस्तार नहीं हुआ है फलतः राष्ट्रीयकृत बैंको से दूर स्थित ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को योजना का यथोचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः ग्रामीण बैंको को भी योजना के अन्तर्गत वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु अधिकृत किया जाना चाहिए क्योंकि इन बैंको की ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंको के अपेक्षाकृत अधिक शाखाएं कार्यरत है।

9-4-3 cpdj , d gLrf' kfyi ; ks grw ykHkdj h ; kst uk, %&

v- dj?kk?kj fuekzk vupku ; kst uk %& इस योजना के तहत बुनकरों को करघा घर निर्माण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 7000/- एवं शहरी क्षेत्रों में 10000/- रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में इस जिले को 40 करघाघर अनुदान देने के लक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिनके विरुद्ध 40 करघाघर स्वीकृत किये जा चुके हैं।

c- egkRek xkakh cpdj chek ; kst uk :- योजनान्तर्गत न्यूनतम 25 बुनकरों के समूह का 80/- प्रति बुनकर प्रीमियम लेकर जीवन बीमा किया जाता है। बीमित बुनकर की सामान्य मृत्यु होने पर 50 हजार, दुर्घटना मृत्यु पर 80 हजार एवं पूर्णतया अपंगता पर 50 हजार तथा एक अंग से अपंग होने पर 25 हजार का बीमित लाभ देय होता है साथ ही बीमित बुनकर को दो बच्चों तक यदि वे 9वीं से 12वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो प्रति तिमाही 300/- रुपये छात्रवृत्ति देय होगी। इस वर्ष 400 का लक्ष्य निर्धारित था जिसे प्राप्त कर लिया जायेगा। अब तक 83 बुनकरों का बीमा किया जा चुका है।

I - LokLFk; chek ; kst uk %& हाथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु वर्ष 2005-06 से स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारम्भ की गयी। इसमें बीमित व्यक्ति के बीमार होने बीमा कम्पनी द्वारा 15000/- रुपये वार्षिक का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है कुल देय

प्रीमियम 1000/- रुपये में से 800/- केन्द्रीय सरकार द्वारा ,100/- राज्य सरकार द्वारा एवं मात्र 100/- रुपये व्यक्तिगत बुनकर द्वारा वहन किये जाते है।

9-4-4 x'g m | ksx ; kst uk

इस योजना के तहत महिलाओं के आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न टेड्स में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है। गत वित्तीय वर्ष में 5 टेड्स में 125 महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया था जिसे अर्जित कर लिया जाएगा। अब तक 101 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

9-4-5 nLrdkjs , o y/kq m | fe; ka dks foi .ku | fo/kk,

जिला उद्योग केन्द्र द्वारा लघु एवं हस्तशिल्पियों एवं दस्तकारों के उत्पादों को मार्केट उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिवर्ष फरवरी माह में उद्योग एवं हस्तशिल्प मेलों का आयोजन किया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में नागौर शहर में रुरल हाट बाजार स्थापित करने का प्रावधान रखा गया है। इस हेतु ख.न. 1171/338/667 व 122 में 7.09 बीघा जमीन का आवंटन करवाया जा चुका है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत डीडवाना और मेडता में भी रुरल हाट बाजार स्थापित किये जाने प्रस्तावित है।

9-4-6 vkVhztu C; kt vupku ; kst uk

विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली आर्टीजन ब्याज अनुदान योजना में आर्टीजन्स क्रेडिट कार्ड से लाभान्वितों को उनके बैंक को ऋण के पेटे भुगतान किये गये ब्याज पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

9-4-7 Lo; | gk; rk | eg | g; ksx vupku

गृह उद्योग योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं का स्वयं सहायता समूह गठन होने के पश्चात प्रत्येक समूह को एक-एक हजार रुपये की समूह विकास सहायता के रूप में दिया जाता है।

9-4-8 jkst xkj esyk

जिले में स्थापित उद्यमों एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में उपलब्ध रोजगार सुविधाओं की जानकारी कर जिले में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु इस पंचवर्षीय योजना में मेलों आयोजित किये जावेगें ताकि शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिल सके तथा उद्यमियों को भी योग्य तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध हो सके तथा बेरोजगारी का निराकरण हो सके।

12-5 | eL; k@ | pko

- ✳ वर्तमान में साल्ट रिफाइनरी की स्थापना लागत बहुत ज्यादा है इस लागत को कम किये जाने की प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं अतः तकनीकी विशेषज्ञों के माध्यम से कम लागत की साल्ट रिफाइनरी स्थापित करने की क्षेत्र में अनवेषण हेतु प्रयासों की आवश्यकता है। इस बाबत इस क्षेत्र में कार्यरत वरिष्ठ उद्यमी श्री रामप्रसाद साबू द्वारा काफी तथ्य इकट्ठे किये गये हैं। उनके आधार पर व्यावहारिक अनवेषण किया जाना उचित रहेगा।
- ✳ नमक रिफाइनरी की स्थापना में उद्यमी के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के साथ-साथ जनस्वास्थ्य को मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। जब तक कम लागत की रिफाइनरी का व्यावहारिक मॉडल नहीं आ जाता है राज्य सरकार को साल्ट रिफाइनरी स्थापित करने हेतु पूँजी निवेश अनुदान समुचित मात्रा में देने पर विचार करना चाहिए।
- ✳ हस्तशिल्प निर्माण हेतु स्थायी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जिसमें निरंतर डिजायन विकास करने वाले सृजकों को भी शामिल किया जावे।